1. मैसर्स सिंघानिया सीमेंट भाटापाड़ा, रायपुर	12.4.92 को वायु अधिनियम के तहत न्यायालय में मामला दायर किया गया।
2. मैसर्स भगत आइरन एंड रि-रोलिंग, दुर्ग	30.6.93 को वायु अधिनियम के तहत न्यायालय में मामला दायर किया गया।
3. मैसर्स छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी, भिलाई	जल अधिनियम, 1974 की धारा 33 के तहत उत्पादन को केवल 8 घंटे तक सीमित करने तथा समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करने के निदेश जारी किए गए हैं। उद्योग ने माननीय उच्च न्यायालय से रोक आदेश ले लिया है।
4. मैसर्स केडिया डिस्टीलरी, दुर्ग	जल अधिनियम की धारा 33 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं। उद्योग ने माननीय उच्च न्यायालय से रोक आदेश ले लिया है।
5. मैसर्स जिन्दल स्ट्रिप्स लि॰	वायु अधिनियम की धारा 33 क के तहत 23.3.94 को नोटिस जारी किया गया।

(ग) जी, हां, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की 17 किस्मों का पता लगाया है और केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार उद्योगों को एक समयबद्ध कार्यक्रम दिया गया है। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की 18 बड़ी/मझौली औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। उक्त सभी इकाइयों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई कर ली है। कोरबा क्षेत्र के लिए "कोरबा कार्य योजना" कार्यान्वित की जा रही है।

पर्यावरण अधिनियम और वन अधिनियम में संशोधन

6610. **श्री जनार्दन यादव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पठारी क्षेत्रों से पत्थरों की ढुलाई पर रोक लगा दी गई है;

(ख) क्या ऐसी रोक लग जाने के कारण हजारों क्रेशर मशीनों पर अब पत्थर तोड़े नहीं जा सकते जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पर्यावरण अधिनियम और वन अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने बिहार के पठारी क्षेत्रों में पत्थरों की ढुलाई पर ऐसी कोई रोक नहीं लगाई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Foreign assistance for development of Western Ghats

6611. SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI RANJAN PRASAD YADAV:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Karnataka Forest Department has received Rupees 93 crores from the Overseas Development Agency, a British voluntary organisation, for the development of the Western Ghats, of which 10% has to be spent on training of the staff working on the project;

(b) whether the Forests Department has started holding training programmes in five-star hotels and sending its officials abroad instead of training them in the project area; and

(c) if so, what steps Government intend to take to ensure that overseas funds for such projects are spent productively and effectively instead of in a lavish and wasteful manner?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) The Overseas Development Administration (ODA), an organisation of the UK Govt., is funding the Western Ghats Forestry Project in Karnataka. The Project has been under implementation since 1992-93 and will be spread over six